

MR. CHAIRMAN : Now we will take up item no. 14.

Shri Subhdh Mohite, you can initiate the discussion till 1730 hrs. Thereafter, half-an-hour discussion will be taken up.

SHRI SUBODH MOHITE (RAMTEK): I beg to move* :

"That the Bill to provide for the establishment of an autonomous Board for all-sided development of all economically backward areas of the country, be taken into consideration. "

सभापति जी, सबसे पहले मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और खास तौर पर आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

जब रीवर का बिल चल रहा था तो उस वक्त मेरा बिल भी आना चाहिए, इसके लिए मैंने इंटरप्शन किया, उसके लिए I feel very sorry. लेकिन मेरे दिल में एक शंका थी कि मुझे जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने इस बिल को कन्सीडर करके डिस्कशन की जो अपोर्चुनिटी दी है, उसके लिए I am very thankful to you.

बैकवर्ड एरिया डवलपमेंट बोर्ड बिल के अपने आपमें एक मायने हैं। इस बिल का एक विशेष महत्व है। यह बिल पूरे हिन्दुस्तान के लिए एक अलग इम्पोर्टेंस रखता है। जिस हिन्दुस्तान देश में हम रहते हैं, इस देश का नाम पूरे वर्ल्ड में है। हिन्दुस्तान की जो परम्परा है, उसको देखते हुए हिन्दुस्तान को पूरे वर्ल्ड में अलग नाम से जाना जाता है। यहां की जो संस्कृति है, यह विभिन्न संस्कृतियों से भरा हुआ देश है और हम देखते हैं कि हर संस्कृति का हजारों साल का इतिहास इस 100 करोड़ की आबादी के देश में है। इसका इतिहास मैं शार्ट में बताना चाहूंगा। I am proud of my country कि हिन्दुस्तान जैसे देश में मैंने जन्म लिया है। जैसा विलास मुत्तेमवार साहब ने बताया कि इस देश का एक इतिहास है। खास तौर से मैं इस शब्द के उमर गौर करना चाहूंगा कि विश्व में हिन्दुस्तान एक ही देश है, जिसके पास बहुत बड़ा इतिहास है। इसी देश में भगवान श्रीकृष्ण ने जन्म लिया, प्रभु रामचन्द्र जी ने इसी देश में जन्म लिया।

*** Moved with the recommendation of the President.**

मुत्तेमवार जी के एक-एक शब्द से मैं सहमत हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा जो संसदीय क्षेत्र है, वह रामटेक है, जो प्रभु राम के नाम से जाना जाता है।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : राम वहां आए थे।

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : मैं स्वयं राम का फालोअर हूँ। मुझे राम भक्त के नाम से जाना जाता है। मैं खुद को राम का भक्त समझता हूँ तो काम भी वैसा होना चाहिए। इसलिए श्रीराम जैसा काम करने के लिए मैं यह बिल खास तौर पर यहां लाया हूँ। इसका आप सब समर्थन करेंगे, इस आशा के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ।

रामराज्य में, प्रभु जब राज करते थे तो राजा से ज्यादा प्रजा श्रेष्ठ थी। राजा का स्थान दूसरा था और प्रजा का उससे ऊपर था। मैंने पहले भी बताया कि हिन्दुस्तान विविध जातियों और धर्मों का देश है। जब-जब देश पर कोई आपत्ति आती है, तो हम सब भाईचारे के नाते अपने-अपने धर्म और जाति भूल जाते हैं और देश पर आए संकट का मुकाबला करने के लिए एक हो जाते हैं। कारगिल का उदाहरण हमारी आंखों के सामने अभी भी है। हम तब देखते थे कि हमारे जवान लड़ रहे हैं, वे यह नहीं सोचते थे कि मैं किस धर्म का हूँ या जाति का हूँ और किसलिए लड़ रहा हूँ। हम सब दूरदर्शन पर उनके इंटरव्यू देखते थे, वे कहते थे कि हम देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं।

हिन्दुस्तान को आजाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना खून बहाया है। लाखों-करोड़ों लाखों इस धरती पर गिरीं। कई लोगों ने लाटियां खाईं, कई लोग मौत के मुंह में चले गए इसलिए कि हमारा देश आजाद हो जाए। हमारे पूर्वजों ने अपनी जानें गंवाईं। उन्होंने एक सपना देखा था कि हम गुलामी में हैं, लेकिन हम गुलामी से जब आजादी में चले जाएंगे तो हमारे बाल-बच्चे सुखी हो जाएंगे। हमारी जान जाए तो जाए, लेकिन हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, वह एक अच्छे सपने के साथ जीएगी। इस आशा में उन लोगों ने अपनी जान गंवाई। उन्होंने सपना देखा, लेकिन जैसा कि कहते हैं सपना सपना ही होता है। आजादी मिली, 10, 20, 40 और अब 53 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन उनका सपना, सपना ही रह गया। उनका दुख, दुख ही रह गया, जो सुख वे चाहते थे, वह नहीं मिला। गरीब गरीब ही रहा और अमीर और अमीर बनता चला गया। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि जब देश आजाद हुआ, तब जो सबसे पहला नेशनल एजेंडा था, मैं 1948 की बात कर रहा हूँ, उसमें नेशनल आब्जेक्टिव रखा गया था कि राष्ट्रीय स्तर पर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, उसको खत्म किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के चेयरमैन प्रिंसीपल एडीशनल सेक्रेटरी, प्लानिंग, को बनाया गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 6 फरवरी, 1977 को दी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में देश के 100 जिलों को चिन्हित किया कि ये ऐसे जिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पिछड़ापन है। उन्होंने जो रिकमंडेशंस दीं, उस पर स्पेशल एक्शन प्लान भी पेंपर के ऊपर तैयार किया गया।

But with a very sad heart I say that no action has been taken till this date. वह कमेटी कहां गई, पता नहीं, उसकी रिपोर्ट कहां गई, पता नहीं, उसकी सिफारिशों का क्या हुआ, यह भी पता नहीं। यह जो बिल पेश किया गया है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जो सबसे पिछड़े क्षेत्र हैं, उनके लिए स्पेशल एक्शन प्लान केंद्र सरकार की तरफ से बनाए जाने की बात है। बाकी सांसद अपने-अपने क्षेत्रों की तरफ से बोलेंगे।

लेकिन मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, वह महाराष्ट्र के विदर्भ एरिया से है और विदर्भ एरिया के भी रामटेक क्षेत्र से है। मैंने जब से होश संभाला है, बीस साल से देख रहा हूँ, राजनीति के एक-एक स्टेप को देख रहा हूँ। राजनेता सफेद कपड़े पहनकर आते हैं और कहते हैं कि हमें विकास करना है, हम विकास कर देंगे, भाग्य देते हैं। मैं इसीलिए सफेद कपड़े नहीं पहनता हूँ। सबसे पहले कहते हैं कि विकास कर देंगे, आप चिंता मत करिए। रामटेक क्षेत्र में माननीय नरसिंहराव जी जो बाद में प्रधान मंत्री बन गए थे, वह वहां आए। वह हमारे प्रभुराम के मंदिर के गये और जनता के सामने बोला कि मैं नरसिंह

राव जी आन्ध्र प्रदेश से भले ही हूँ लेकिन आप मुझे चुनकर लाएं, मैं रामटेक क्षेत्र का पूरा विकास कर दूंगा। जिस आदमी ने प्रभु राम की सौगंध खाई, रामटेक के भोले-भाले लोग थे, उन्होंने विश्वास कर लिया। उनको लगा कि प्रभु रामचन्द्र की कसम खाई है, हमें धोखा नहीं हो सकता। वह चुनकर आ गये और चुनकर आने के बाद

लोग ढूढ़ने लगे कि कहां गये। वह तो प्राइम मिनिस्टर बन गये। प्रभु रामचन्द्र की कसम जगह पर रह गई। नरसिंह राव जी प्रधान मंत्री बन गये। विकास का सपना जगह पर ही रह गया। लोग बेचारे आंसू बहाते रह गये। मैं खास तौर पर बोलना चाहता हूँ कि बीस साल से विकास के नाम पर राजनीति सिर्फ चर्चा, चर्चा और चर्चा हो गई है। मैं समझता हूँ कि सदन में इस चर्चा के विषय को पूर्ण विराम देने की जरूरत है और ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

जैसा हिन्दुस्तान का इतिहास है, उसी प्रकार महाराष्ट्र का भी अजीबोगरीब इतिहास है। देश जब से स्वतंत्र हुआ, रामदास आठवले जी वहां के जाने-माने नेता हैं और पहले कांग्रेस के नेता थे और अभी एन.सी.पी. में हैं। पहले नेशनलाइड नेता थे, अब नेशनल कांग्रेस में हैं। आजादी के बाद 1960 में जब एक सवाल आया कि महाराष्ट्र क्या है। उस टाइम काफी चर्चाएं हुई हैं और बताया कि महाराष्ट्र को अलग बना देंगे। उसके बाद झगड़ा चला कि विदर्भ कहां जाएगा? उस समय सखा पाटिल जी वहां के केंद्रीय मंत्री जी थे। उन्होंने बोला कि विदर्भ को हम मध्य प्रदेश में डाल देंगे और गुजरात और बम्बई को करैक्ट कर देंगे। मोरार जी देसाई ने यह कांसेप्ट दिया था कि गुजरात और बम्बई को जोड़कर एक महाराष्ट्र बनाएंगे लेकिन मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हम जिन्हें भगवान समझते हैं, हमारे बाला साहिब ठाकरे जी के पिताजी प्रभुदत्त ठाकरे जी ने सबसे पहले यह बात रखी कि विदर्भ को मध्य प्रदेश से नहीं जोड़ेंगे बल्कि महाराष्ट्र से जोड़ा जाएगा। उस समय बाला साहेब ठाकरे जी छोटे थे। इस पर हल्ला चालू हो गया, झगड़ा चालू हो गया, रक्तपात, खून-खराबा चालू हो गया, लाठीचार्ज चालू हो गया। उसमें 105 लोग मर गये। 105 लोग मरने के बाद 1960 में संयुक्त महाराष्ट्र फॉर्म हो गया और संयुक्त महाराष्ट्र जब फॉर्म हुआ तब महाराष्ट्र की जनता के साथ एक वादा किया गया। वह वादा यह था कि हम महाराष्ट्र को पूरा सुजलाम सुफलाम कर देंगे लेकिन जिस वादे के साथ 1960 में संयुक्त महाराष्ट्र बनाया गया,

काश! वह वायदा सच हो जाता और यह विधेयक लाने की सदन में जरूरत नहीं पड़ती। मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूँ। जब संयुक्त महाराष्ट्र की मूवमेंट शुरू हुई थी, उस समय बालासाहेब ठाकरे छोटे थे, लेकिन वे उसी विचार को लेकर, उसी कन्सेप्ट को लेकर आज तक अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया, जिस तरह से महाराष्ट्र को जोड़ा है, जिस तरह से विदर्भ को जोड़ा है, उसमें 105 लोगों की जानें गई हैं, इसलिए फिर विदर्भ को तोड़कर लोगों की जानें नहीं गंवाना चाहते हैं, खून-खराबा नहीं करना चाहते हैं। विदर्भ के सवाल पर हमें एनालैसिस करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। मैं यहां एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, हमारे दोस्त जो उधर बैठे हैं, मैं उनसे माफी मांगता हूँ और मैं जो भी बात कहूंगा, वह सच कहूंगा। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ। पांच साल पीछे के इतिहास को देखें, तो 45 सालों में उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। उस क्षेत्र का विकास न होने में जो सबसे पहली बात सामने आई, वह यह थी कि राज्य सरकार के फंड्स का समानान्तर वितरण नहीं हुआ। मैंने प्रश्न किया - यह डिस्ट्रिब्यूशन किसके हाथ में है? जवाब आया - यह राज्य सरकार के हाथ में है। मैंने फिर प्रश्न किया - सरकार किसकी था? इसका जवाब रामदास आठवले जी देंगे - कांग्रेस की। 45 साल **unequal distribution of Funds** की वजह से विदर्भ पिछड़ा रहा है। कांग्रेस की सरकार या किसी भी सरकार ने इस विषय को गम्भीरता से नहीं लिया। गम्भीरता से नहीं लेने के कारण ही वह क्षेत्र धीरे-धीरे पिछड़ता गया। 1960 के बाद 1982 में, 22 सालों के बाद, एक नेता को लगा कि इनके साथ अन्याय हुआ है। ज्यादा अन्याय होने पर लोग मर जायेंगे। इसलिए उन्होंने दांडेकर समिति का गठन किया और उसको यह जिम्मेदारी दी कि पता लगाया जाए कि उस क्षेत्र के साथ कितना अन्याय किया गया है, क्योंकि उनको विकास के लिए पैसा नहीं दिया गया। दांडेकर समिति की रिपोर्ट 1984 में आई। उस रिपोर्ट के आने के बाद बम्ब ब्लास्ट हो गया। उस रिपोर्ट में बताया गया कि 37.32 प्रतिशत यानि एक-तिहाई से भी ज्यादा, अन्याय किया गया है। 1984 में रिपोर्ट आने के बाद निर्णय हुआ कि टोटल बजट का 85 फीसदी ऐसे क्षेत्रों को दिया जाएगा, जहां बैकलाग ज्यादा है और 15 प्रतिशत अन्य क्षेत्रों को दिया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस का उल्टा कर दिया। 85 प्रतिशत राशि अन्य क्षेत्रों को दी और 15 प्रतिशत राशि बैकलाग क्षेत्रों को दी। इस प्रकार बैकलाग बढ़ता गया और हम विकास की बात करते रहे। फिर महाराष्ट्र के निर्माण के बाद यश्वन्तराव चव्हाण जी उस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा - मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ और मैं आप लोगों के साथ एक वायदा करना चाहता हूँ।

उन्होंने कहा कि मैं एक एग्रीमेंट करता हूँ और उन्होंने विदर्भ के लोगों के साथ नागपुर एग्रीमेंट कर लिया। इसमें डिंसाइड किया गया कि संविधान की धारा 371(2) के अन्तर्गत विदर्भ क्षेत्र के लिए वैधानिक विकास मंडल बनाया जायेगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Subodh Mohite, you can continue next time.

17.31 hours